

केन्द्र सरकार की योजनाएँ : पूर्ण परिचय

► नमांगि गंगे योजना

- शुभारंभ - 10 जुलाई, 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा
- उद्देश्य - गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु

► प्रधानमंत्री जन-धन योजना

- शुभारंभ - 28 अगस्त, 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा
- उद्देश्य - सभी परिवारों में कम-से-कम एक बैंक खाता
- 26 फरवरी, 2020 तक **38.18 करोड़** खाते खोले जा चुके हैं
- लाभ - 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा

► मेक इंन इंडिया

- शुभारंभ - 25 सितम्बर, 2014 को
- उद्देश्य - देश में मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा

► सांसद आदर्श ग्राम योजना

- शुभारंभ - 11 अक्टूबर, 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर
- उद्देश्य - प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक **तीन गाँव** तथा वर्ष 2024 तक कुल **8 गाँवों** को गोद लेकर विकसित करना है।

► मिशन इंद्रधनुष अभियान

- शुभारंभ - 25 दिसम्बर, 2014 को केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा
- उद्देश्य - 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना
- इस योजना के अंतर्गत **7 बीमारियों** (डिफ्यूरिया, काली खाँसी, टिनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस 'बी') के लिए टीकाकरण होगा।

► हृदय योजना

- शुभारंभ - 21 जनवरी, 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा
- **HRIDAY** : Heritage City Development and Augmentation Yojana
- उद्देश्य - चयनित **12 शहरों** की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना

► बेटी बच्चओं, बेटी पढ़ाओ योजना

- शुभारंभ - 22 जनवरी, 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा
- उद्देश्य - लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना

► प्रधानमंत्री 'मुद्रा' योजना

- शुभारंभ - 8 अप्रैल, 2015 को
- **MUDRA** : Micro Units Development & Refinance Agency
- उद्देश्य - सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण (प्रकार-शिशु, किशोर तथा तरुण) उपलब्ध कराना
- शिशु के तहत **50 हजार**, किशोर के तहत **5 लाख** तथा तरुण के तहत **10 लाख** रुपए तक के लोन देने का प्रावधान है।

► उजाला योजना

- शुभारंभ - 1 मई, 2015 को
- **UJALA** : Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All
- उद्देश्य - बिजली खपत के लिए LED बल्बों का कम मूल्य पर वितरण

► अटल पेंशन योजना

- शुभारंभ - 9 मई, 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा
- इसके अंतर्गत **18 से 40 वर्ष** के व्यक्ति बैंक में जमा किये गए रुपये के आधार पर **1 हजार से 5 हजार** तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है।

► अमरुत योजना

- शुभारंभ - 24 जून, 2015 को
- **AMRUT** : Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation
- इस योजना के अंतर्गत **100 स्मार्ट सिटी** बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और **2022** तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है।

► स्मार्ट सिटी मिशन

- शुभारंभ - 25 जून, 2015 को
- उद्देश्य - 100 शहरों का चयन कर विकास करना (सिंगापुर के सहयोग से)

► प्रधानमंत्री आवास योजना

- शुभारंभ - 25 जून, 2015 को
- उद्देश्य - 2022 तक 2 करोड़ नये घरों का निर्माण करना

► डिजिटल इंडिया मिशन

- शुभारंभ - 1 जुलाई, 2015 को
- उद्देश्य - सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना

► प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

- शुभारंभ - 1 जुलाई, 2015 को की गई थी।
- उद्देश्य - किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना

► स्कील इंडिया मिशन

- शुभारंभ - 15 जुलाई, 2015 को
- उद्देश्य - 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना

► दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

- शुभारंभ - 25 जुलाई, 2015 को की गई थी।
- उद्देश्य - सभी गाँवों का विद्युतीकरण करना

- **सागरमाला परियोजना**
 - शुभारंभ - 31 जुलाई, 2015 को
 - उद्देश्य - बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क/रेल परिवहन से जोड़ना
- **उदय (UDAY) योजना**
 - शुभारंभ - 5 नवम्बर, 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा
 - **UDAY** : Ujwal Discom Assurance Yojana
 - उद्देश्य - विजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु
 - इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखण्ड है।
- **श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबंन मिशन**
 - शुभारंभ - 22 फरवरी, 2016 का
 - उद्देश्य - गाँवों का कलस्टर आधारित विकास
- **सेतु भारतम् योजना**
 - शुभारंभ - 4 मार्च, 2016 को केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा
 - उद्देश्य - राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए
- **स्टैण्ड अप इंडिया**
 - शुभारंभ - 5 अप्रैल, 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा
 - उद्देश्य - नई कंपनियाँ स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण
- **उडान (UDAN) योजना**
 - शुभारंभ - 27 अप्रैल, 2017 को (पूरा नाम-उड़े देश का आम नागरिक)
 - उद्देश्य - देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना
- **दीक्षा पोर्टल**
 - शुभारंभ - 5 सितम्बर, 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा
 - यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है।
- **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना**
 - शुभारंभ - 1 मई, 2016 को
 - उद्देश्य - BPL परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन देना
 - इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा BPL परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- **प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना -आयुष्मान भारत**
 - शुभारंभ - 23 सितम्बर, 2018 को झारखण्ड की राजधानी राँची से
 - उद्देश्य - गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा
- **वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना**
 - शुभारंभ - 1 जनवरी, 2017 को भारतीय जीवन निगम (LIC) द्वारा
 - उद्देश्य - 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी।
- **दीन दयाल उपाध्याय 'स्पर्श (SPARSH)' योजना**
 - शुभारंभ - 3 नवम्बर, 2017 को
- **SPARSH** : Scholarship for Promotion of Aptitude & Research in Stamps as a Hobby
- 6ठी-9वीं के बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रूची हेतु छात्रवृत्ति योजना
- लाभ - अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6000 रु. प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति
- **प्रधानमंत्री वय बंदना योजना**
 - शुभारंभ - 21 जुलाई, 2017
 - उद्देश्य - 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8 प्रतिशत की गारंटीशुदा रिटर्न
- **प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - 'सौभाग्य'**
 - शुभारंभ - 25 सितम्बर, 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा
 - उद्देश्य - देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना
- **PM-किसान सम्मान निधि योजना**
 - शुरूआत - 24 फरवरी, 2019 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा
 - उद्देश्य - देश के सभी किसानों को 6000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता।
 - यह सहायता दो-दो हजार रुपये की तीन समान किस्तों में दी जाएगी।
- **प्रधानमंत्री श्रम योगी मानवधन योजना**
 - शुभारंभ - 15 फरवरी, 2019 को
 - योजना के पात्र - 18-40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15000 रुपया या उससे कम है।
 - लाभ - 60 वर्ष की आयु होने पर 3000 रुपये की मासिक पेंशन
- **प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना**
 - शुभारंभ - 12 सितम्बर, 2019 को राँची (झारखण्ड) में
 - लाभ - 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3000 प्रति माह पेंशन
 - पात्र - 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है।
- **अग्निपथ योजना**
 - योजना की घोषणा - 14 जून, 2022
 - योग्यता - 10वीं-12वीं पास (आयु - 17.5 से 21/23 वर्ष)
 - इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए तीनों सेनाओं (थल, जल, वायु) में भर्ती किया जायेगा, जिन्हें 'अग्निवीर' कहा जायेगा।
 - चार साल पर अग्निवीरों को सेवा निधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपये का भुगतान किया जायेगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को CAPF एवं असम राइफल्स में 10% आरक्षण दिया जायेगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन स्थायी रूप से किया जायेगा।
- **पीएम विश्वकर्मा योजना**
 - शुभारंभ - 17 सितम्बर, 2023 (नई दिल्ली से)
 - उद्देश्य - पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराना है।
 - इसके लिए 13000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।
 - इसके तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है।

केन्द्रीय योजनाएँ/कार्यक्रम/अभियान : एक जजर में

योजना	शुरूआत		
■ प्रधानमंत्री जन-धन योजना	28 अगस्त, 2014	■ पीएम स्वनिधि योजना	1 जून, 2020
■ मेक इन इंडिया	25 सितम्बर, 2014	■ गरीब कल्याण रोजगार योजना	20 जून, 2020
■ स्वच्छ भारत मिशन	2 अक्टूबर, 2014	■ नई शिक्षा नीति 2020	30 जुलाई, 2020
■ मिशन इंद्रधनुष योजना	15 दिसम्बर, 2014	■ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन	15 अगस्त, 2020
■ बेटी बच्चाओं-बेटी पढ़ाओं	22 जनवरी, 2015	■ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	10 सितम्बर, 2020
■ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना	8 अप्रैल, 2015	■ आयुष्मान सहकार योजना	19 अक्टूबर, 2020
■ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	9 मई, 2015	■ आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना	12 नवम्बर, 2020
■ अटल पेंशन योजना	9 मई, 2015	■ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	24 नवम्बर, 2020
■ प्रधानमंत्री आवास योजना	25 जून, 2015	■ PM-वाणी योजना	9 दिसम्बर, 2020
■ अमरूत योजना (AMRUT)	25 जून, 2015	■ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0	15 जनवरी, 2021
■ डिजिटल इंडिया मिशन	1 जुलाई, 2015	■ ग्राम उजाला योजना	19 मार्च, 2021
■ स्कील इंडिया मिशन	15 जुलाई, 2015	■ जल शक्ति अभियान : कैच द रेन	22 मार्च, 2021
■ दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	25 जुलाई, 2015	■ PM-युवा योजना	29 मई, 2021
■ भारतमाला परियोजना (संबंध-राष्ट्रीय राजमार्ग)	31 जुलाई, 2015	■ SAGE कार्यक्रम	4 जून, 2021
■ वन रैक-वन पेंशन योजना	7 नवम्बर, 2015	■ 'सुरक्षित हम सुरक्षित तुम' अभियान	8 जून, 2021
■ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	13 जनवरी, 2016	■ 'जान है तो जहान है' अभियान	21 जून, 2021
■ स्टार्ट-अप इंडिया	16 जनवरी, 2016	■ NIPUN भारत कार्यक्रम	3 जुलाई, 2021
■ श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूबन मिशन	21 फरवरी, 2016	■ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0	10 अगस्त, 2021
■ सेतु भारतम् परियोजना (संबंध-रेलवे क्रॉसिंग)	4 मार्च, 2016	■ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन	27 सितम्बर, 2021
■ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना	1 मई, 2016	■ स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0	1 अक्टूबर, 2021
■ उड़ान योजना (UDAN)	27 अप्रैल, 2017	■ AMRUT 2.0	1 अक्टूबर, 2021
■ प्रधानमंत्री वय वंदना योजना	21 जुलाई, 2017	■ पीएम पित्र योजना	6 अक्टूबर, 2021
■ प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - 'सौभाग्य'	25 सितम्बर, 2017	■ प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना	13 अक्टूबर, 2021
■ दीनदयाल 'स्पर्श' योजना (SPARSH)	3 नवम्बर, 2017	■ SMILE योजना (सामाजिक न्याय मंत्रालय)	12 फरवरी, 2022
■ भारतनेट योजना	13 नवम्बर, 2017	■ SEED योजना (सामाजिक न्याय मंत्रालय)	16 फरवरी, 2022
■ राष्ट्रीय पोषण मिशन	30 नवम्बर, 2017	■ AVSAR योजना (भारतीय विमानपतन प्राधिकरण)	8 अप्रैल, 2022
■ खेलो इंडिया स्कूल गेम्स	31 जनवरी, 2018	■ स्वनिधि से समृद्धि योजना	12 अप्रैल, 2022
■ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन	1 फरवरी, 2018	■ SHRESHTA योजना (सामाजिक न्याय मंत्रालय)	3 जून, 2022
■ वन धन योजना	14 अप्रैल, 2018	■ अग्निपथ योजना	14 जून, 2022
■ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB)	1 सितम्बर, 2018	■ प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना	14 जून, 2022
■ पी-एम आशा (PM-AASHA)	12 सितम्बर, 2018	■ RAMP योजना	30 जून, 2022
■ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-आयुष्मान भारत	23 सितम्बर, 2018	■ PM SHRI योजना	5 सितम्बर, 2022
■ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना	15 फरवरी, 2019	■ युवा 2.0 (शिक्षा मंत्रालय)	2 अक्टूबर, 2022
■ PM-किसान सम्पादन निधि योजना	24 फरवरी, 2019	■ टेली-MANAS	10 अक्टूबर, 2022
■ प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना	23 जुलाई, 2019	■ मिशन LiFE (पीएम द्वारा केवड़िया, गुजरात से)	20 अक्टूबर, 2022
■ जल जीवन मिशन	15 अगस्त, 2019	■ डिजिटल शक्ति 4.0 (राष्ट्रीय महिला आयोग)	16 नवम्बर, 2022
■ प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना	12 सितम्बर, 2019	■ अमृत भारत स्टेशन योजना (रेल मंत्रालय)	27 दिसम्बर, 2022
■ अटल भू-जल योजना	25 दिसम्बर, 2019	■ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना	11 जनवरी, 2023
■ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना	25 मार्च, 2019	■ आरोग्य मैत्री	13 जनवरी, 2023
■ स्वामित्व योजना	24 अप्रैल, 2020	■ जल जन अभियान	16 फरवरी, 2023
■ आत्मनिर्भर भारत अभियान	12 मई, 2020	■ 75/25 पहल (स्वास्थ्य मंत्रालय)	17 मई, 2023
■ वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना	1 जून, 2020	■ अमृत धरोहर योजना	5 जून, 2023

राज्य सरकार योजनाएँ : 2023-24

राज्य	योजना/कार्यक्रम	मुख्य बिन्दु/उद्देश्य
उत्तर प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> ■ डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना ■ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना ■ पंचामृत योजना ■ नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना ■ नंदिनी कृषक समृद्धि योजना ■ बाल श्रमिक विद्या योजना 	<p>राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुँच के लिए।</p> <p>इसके तहत दी जाने वाली राशि को 15000 के स्थान पर 25000 देने की घोषणा की गई है।</p> <p>इसका उद्देश्य गन्ने की खेती में नई तकनीक का प्रयोग कराना है।</p> <p>दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्पादकों को उचित मूल्य पर दुग्ध बेचने का अवसर हेतु।</p> <p>गोवंशीय पशुओं के दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने और किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए।</p> <p>8 से 18 वर्ष की आयु में बाल श्रमिकों, अनाथों, श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा हेतु।</p>
मध्य प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> ■ लाडली बहना योजना ■ लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 ■ मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना ■ मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना ■ मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना ■ ई-स्कूटी योजना ■ मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना 	<p>इसका तहत गरीब बहनों को प्रतिमाह 1000 रु. की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।</p> <p>बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए।</p> <p>यह योजना 18 से 29 वर्ष के युवाओं के लिए शुरू की गई है। इसके तहत चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के साथ 8 से 10 हजार का भत्ता मिलेगा।</p> <p>किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए 50% सब्सिडी पर 3 हॉर्सपावर का कृषि पंप प्रदान करना।</p> <p>मॉब लिंचिंग की घटना में पीड़ित की मौत होने पर परिवार को 10 लाख का मुआवजा।</p> <p>इसके तहत स्कूल में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली 1 छात्र-छात्रा को स्कूटी दी जायेगी।</p> <p>इसमें 18 वर्ष की उम्र के बाद अनाथ बच्चों को प्रतिमाह 5000 रु. की सहायता दी जायेगी।</p>
छत्तीसगढ़	<ul style="list-style-type: none"> ■ मुख्यमंत्री मितान योजना ■ मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना ■ हमर सुधर लायक अभियान ■ ग्रामीण आवास न्याय योजना 	<p>इसके तहत नागरिक घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।</p> <p>राज्य महिला आयोग द्वारा महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु।</p> <p>इसका उद्देश्य एक सर्वेक्षण के माध्यम से पहचाने गए 1800 कुपोषित बच्चों को सुपोषित बच्चों की श्रेणी में लाना है।</p> <p>इस योजना का उद्देश्य राज्य में बेघर ग्रामीण लोगों को घर उपलब्ध कराना है।</p>
ओडिशा	<ul style="list-style-type: none"> ■ मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना ■ अबाधा योजना ■ एकाग्र परियोजना ■ मिशन शक्ति स्कूटर योजना ■ अमा पोखरी योजना ■ मो जंगल जामी योजना 	<p>माताओं किशोरियों और बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए।</p> <p>इसके तहत सरकार ने पुरी को विश्व धरोहर में बदलने के लिए 1000 करोड़ रूपये दिए हैं।</p> <p>इसका उद्देश्य ओडिशा के प्राचीन मर्दियों का विकास करना है।</p> <p>लाभार्थियों को 1 लाख रूपये तक के बैंक ऋण पर व्याज सहायता प्रदान करने के लिए।</p> <p>राज्य के सभी 115 शहरी निकायों में लगभग 2000 बड़े जल निकायों को कायाकल्प हेतु।</p> <p>राज्य भर में आदिवासी समुदायों और बनवासियों के बीच वन अधिकारों को बढ़ावा देने हेतु।</p>
कर्नाटक	<ul style="list-style-type: none"> ■ गृह लक्ष्मी योजना ■ अन्न भाग्य योजना ■ शक्ति योजना 	<p>इसके तहत एक घर की महिला मुखिया को प्रति माह 2000 रु. की सहायता मिलेगी।</p> <p>इसके तहत लाभार्थियों को अतिरिक्त 5 किलो चावल के बदले भुगतान का निर्णय हुआ है।</p> <p>इस योजना के तहत महिलाएं राज्य सरकार की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी।</p>
गुजरात झारखण्ड	<ul style="list-style-type: none"> ■ SAUNI योजना ■ अबुआ आवास योजना ■ मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 	<p>किसानों को कृषि और सिंचाई की जरूरतों की पूर्ति के लिए दिन में बिजली की आपूर्ति हेतु।</p> <p>इसका उद्देश्य 15000 करोड़ रूपये की लागत से अगले दो वर्षों में जरूरतमंदों के लिए घर उपलब्ध कराना है।</p> <p>इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन की सुविधा को आसान बनाना है।</p>
तेलंगाना	<ul style="list-style-type: none"> ■ गीता कार्मिकुला बीमा योजना ■ आसरा पेंशन योजना 	<p>इसके तहत ताड़ी निकालने वालों को 5 लाख रूपये का बीमा कवर दिया जायेगा।</p> <p>यह बुद्धों, विधवाओं और बीड़ी श्रमिकों के लिए पेंशन की कल्याणकारी योजना है।</p>

राज्य	योजना/कार्यक्रम	मुख्य बिन्दु/उद्देश्य
राजस्थान	<ul style="list-style-type: none"> ■ ईंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना ■ मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना ■ ट्रांसपोर्ट वाडचर योजना ■ महिला निधि योजना ■ मुख्यमंत्री अनुप्रति कोंचिंग योजना 	राज्य के 1.3 करोड़ महिलाओं को 3 वर्ष की डाटा सुविधा के साथ स्मार्टफोन दिए जाएंगे। इसके तहत पशुपालकों को 2 पशु बीमा कवर के साथ 80 हजार रु. की सहायता दी जायेगी। 10 किमी. से दूर स्थित कॉलेज के छात्राओं को प्रतिदिन 20 रु. की राशि बैंक खाते में दी जायेगी। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, SC तथा ST के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु।
तमिलनाडु	<ul style="list-style-type: none"> ■ कलैगनार महिला पात्रता योजना 	राज्य की एक करोड़ महिला लाभार्थियों को प्रति माह 1000 रु. का भुगतान किया जायेगा।
महाराष्ट्र	<ul style="list-style-type: none"> ■ लेक लड़की योजना ■ नमो शेतकरी महासम्मान योजना ■ विठ्ठल रुक्मिणी वारकरी बीमा छत्र योजना 	इसके तहत सरकार बालिकाओं वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके तहत राज्य के एक करोड़ से अधिक किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रु. दिया जायेगा। इसके तहत राज्य के अषाढ़ी वारकरियों (भगवान विठ्ठल के अनुयायियों) के कल्याण के लिए बीमा प्रदान किया जायेगा, ताकि उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके।
हरियाणा	<ul style="list-style-type: none"> ■ चिराग योजना ■ चारा-बिजाई योजना ■ एक ब्लॉक, एक उत्पाद योजना 	इसके तहत 1.8 लाख वार्षिक से कम आय वाले परिवार के बच्चों को कक्षा दूसरी से बारहवीं तक निजी स्कूल में मुफ्त प्रवेश दिया जायेगा। चारा देने और आपूर्ति करने वाले किसानों को 10000 प्रति एकड़ की सहायता दी जायेगी। ग्रामीण स्तर पर छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने तथा ब्लॉक को औद्योगिक दृष्टि से जोड़ना।
गोवा	<ul style="list-style-type: none"> ■ गृह आधार योजना 	गृहणियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए।
आंध्र प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> ■ जगन्ना अम्मा वोडी योजना ■ YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना 	शिक्षा को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। इस योजना के तहत 42 लाख माताओं को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता 6392 करोड़ रूपये है। इसके तहत प्रत्येक मछुआरा परिवार को स्थायी आजीविका हेतु 10000 रु. दिया जाता है।
उत्तराखण्ड	<ul style="list-style-type: none"> ■ उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना ■ हिम प्रहरी योजना ■ A-HELP कार्यक्रम ■ मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना 	खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। यह योजना पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए है जिसका उद्देश्य लोगों के पलायन को रोकना है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन संबंधी गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए। इसके अंतर्गत युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध हो, इसके लिए ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई जायेगी तथा विदेशों में रोजगार उपलब्ध करवाने वाले कंपनियों को प्रस्ताव भेजा जायेगा।
हिमाचल प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> ■ सशक्त महिला ऋण योजना ■ मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना ■ मुख्यमंत्री सबल योजना ■ ईंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना 	महिलाओं की उनकी उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को साकार करने हेतु। इसके तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को 1% ब्याज दर पर लोन दिया जायेगा। हर बच्चे को गुणवत्ता वाली शिक्षा स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु। इसमें महिलाओं को पहले 4 माह 1500 रु. उसके बाद 9000 रु. एक साथ दिया जायेगा।
लद्दाख	<ul style="list-style-type: none"> ■ कुनस्योम योजना 	विकलांग व्यक्तियों को 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण व तकनीक उपलब्ध कराने हेतु।
असम	<ul style="list-style-type: none"> ■ आयुष्मान असोम योजना ■ स्व-निर्भर नारी योजना ■ अरुणोदय 2.0 योजना 	इसके तहत 26 लाख परिवारों के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रु. का कैशलेस इलाज दी जायेगी। यह असम में स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने की योजना है। राज्य के महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से 1250 रु. की आर्थिक सहायता प्रदान करना।
बिहार	<ul style="list-style-type: none"> ■ मिशन दक्ष ■ मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना 	1 दिसम्बर, 2023 को बिहार शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक रूप से कमजोर 25 लाख विद्यार्थियों को सलाह देने के लिए 'मिशन दक्ष' लांच किया है। इसके तहत राज्य सरकार एक बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला या पुरुष को नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रूपये की राशि देगी।
पंजाब	<ul style="list-style-type: none"> ■ लोक मिलनी योजना ■ स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट 	जन संपर्क बढ़ाना तथा राज्य के लोगों की शिकायतों के निवारण हेतु मंच प्रदान करना। कक्षा 9 से 12 तक के सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में अपग्रेड किया जायेगा।
त्रिपुरा	<ul style="list-style-type: none"> ■ CM चां श्रमि कल्याण प्रकल्प योजना 	राज्य के 7000 चाय बगान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए।